



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062023-246728
CG-DL-E-21062023-246728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2619]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945

No. 2619]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2023

का.आ. 2734(अ).—अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ.1114 (अ), तारीख 12 मार्च, 2018 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा महानदी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन अंतर्राज्यीय महानदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण को अपनी रिपोर्ट और यथा अपेक्षित विनिश्चय को तारीख 11 मार्च 2021 को या उससे पूर्व देना अपेक्षित था;

और अपरिहार्य कारणों से उक्त अधिकरण अपनी रिपोर्ट तीन वर्ष की उक्त अवधि में प्रस्तुत नहीं कर सका था;

और उक्त अधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और केंद्रीय सरकार ने दिनांक 3 जून, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2176 (अ.) के माध्यम से उक्त अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत किए जाने की अवधि को दो वर्षों अर्थात् 11 मार्च, 2023 तक या उक्त अधिनियम की धारा 5 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निर्णय और विनिश्चय प्रस्तुत किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया था;

और उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार उक्त अधिकरण द्वारा पहली नियमित सुनवाई की तारीख अर्थात् 14 दिसंबर, 2019 पर विचार करे जो कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए अधिकरण की स्थापना की प्रभावी तारीख के रूप में है;

और उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से मार्च 2020 से जून 2021 तक की अवधि को कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए अधिकरण के लिए इस अवधि को गैर-कार्यात्मक मानने पर विचार करने का अनुरोध किया है;

और केंद्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह के मामलों में दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 14 दिसंबर, 2019 होगी और उक्त अधिकरण के लिए मार्च, 2020 से जून, 2021 (सोलह माह) की अवधि को अपरिहार्य कारणों से गैर-कार्यात्मक माना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि जो उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आवंटित की गई है, इस अवधि को 13 अप्रैल, 2024 को समाप्त माना जाएगा;

अतः, अब केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानदी जल विवाद अधिकरण की रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत की जाने की अवधि को 14 अप्रैल, 2024 की प्रभावी तारीख से दो वर्ष की अवधि अर्थात् 13 अप्रैल, 2026 तक या इससे पहले, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

[सं. एन.70012/1/2021-बी.एम.अनुभाग-ज.सं.मं.]

आनंद मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2023

S.O. 2734(E).—Whereas, the Mahanadi Water Disputes Tribunal (hereafter in this notification referred to as the said Tribunal) was constituted on the 12th March, 2018 vide notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation number S.O. 1114(E), dated the 12th March, 2018, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter in this notification referred to as the said Act), for the adjudication of water disputes regarding inter-State river Mahanadi and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision as required under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, that is, on or before the 11th March, 2021;

And whereas, due to unavoidable reasons, the said Tribunal could not submit its report within the said period of three years;

And whereas, the said Tribunal requested the Central Government to extend the said period for submission of report and decision thereon;

And whereas, the Central Government vide notification number S.O. 2176 (E), dated the 3rd June, 2021, extended the period for submission of report and decision thereon by the said Tribunal for a period of two years upto the 11th March, 2023 or till the submission of report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act, whichever is earlier;

And whereas, the said Tribunal has requested the Central Government to consider the date of holding the first regular hearing by the said Tribunal, that is, the 14th December, 2019 as the effective date of setting up of the Tribunal for the purposes of sub- section (2) of section 5 of the said Act;

And whereas, the said Tribunal has also requested the Central Government to consider the period from March 2020 to June 2021 due to COVID-19 pandemic, as non-functioning and embellishing period for the Tribunal;

And whereas, the Central Government, having regard to the direction given by the Hon'ble Supreme Court in similar matters, has decided that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 14th December, 2019 and period from March, 2020 to June, 2021 (sixteen months) shall be treated as non- functional and embellishing period for the said Tribunal due to unavoidable reasons and the three-year period which is allocated under sub-section (2) of section 5 of the said Act be deemed to expire on 13th April, 2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the proviso to sub- section (2) of the section 5 of said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Mahanadi Water Disputes Tribunal for a period of two years with effect from the 14th April, 2024, that is, on or before the 13th April, 2026, or till the submission of report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. N-70012/1/2021-BM Section-MOWR]

ANAND MOHAN, Jt. Secy.